1	2	3	4	5
24	Uttar Pradesh	4920.00	3700.00	100000.00
25	West Bengal	1575.00	1100.00	55000.00
26	A & N Islands	449.05	6.00	3500.00
27	Chandigarh	225.00	0.00	500.00
28	D & N Haveli	200.00	12.00	1100.00
29	Daman & Diu	20.00	1.00	150.00
30	Delhi	278.00	60.00	2000.00
31	Lakshadweep	16.50	4.00	50.00
32	Pondicherry	73.00	4.00	200.00
	TOTAL	67672.55	16000.00	1190000.00

* — Figures available as per State Plan discussions in the Planning Commission.

गुजरात में औद्योगिक एककों के संबंध में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

1708. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **पर्यावरण** और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारा विकास प्राधिकरण, गुजरात के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक एककों के संबंध में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के मामले केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के संबंध में कितने प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं ;

(ग) अभी तक कितने मामले लंबित है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) प्रमाण पत्र कब तक जारी कर दिए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एक औद्योगिक यूनिट की स्थल स्वीकृति संबंधी एक मामला लंबित है ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान दो परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी ।

(ग) और (घ) स्थल स्वीकृति संबंधी केवल एक ही मामला लंबित है। परियोजना प्राधिकरण ने स्पष्टीकरण एवं अपेक्षित ब्यौरा भेज दिया जिनकी जांच की जा रही है ।

Garbage disposal problem in New Delhi

1709. SHRI M. A. BABY : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Government are aware about the garbage disposal problem in New Delhi and surrounding areas as reported in Times of India dated 3rd April, 1993; and